(b) In view of the reply to 'a' above this does not arise.

(c) The prices of Khadi have increased due to increase in the cost of raw material, labour and transportation charges etc. However, there is no adverse effect on sales of Khadi.

(d) In view of the reply to 'c' above this does not arise.

राष्ट्रीय नवीकरण कोष से श्रमिकों को बकाया राशियों का भुगतान

1715. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन बी० आई० एफ० आर०/ए० ए० आई० एफ० आर० के परिसमापन संबंधी मत के पश्चात उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापक की नियुक्ति की कार्यवाही में होने वाले विलंब को देखते हुए श्रमिकों को राष्ट्रीय नवीकरण कोष से उनके देय अवशेषों के बराबर राशि उपलब्ध कराने एवं बाद में परिसमापक से उक्त राशि वापस प्राप्त करने की कार्यवाही करने का विचार रखती है,

(ख) यदि नहीं, तो परिसमापक की नियुक्ति में विलंब को मद्दे नजर रखते हुए सरकार श्रमिकों के हित में क्या कदम उठाने का विचार रखती है, और

(ग) क्या यह आवश्यक नहीं है कि रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम में परिसमापक की नियुक्ति के उपबंधों को शामिल करके इसमें संशोधन कर दिया जाए ताकि एक ही समय पर निपटारा हो जाए जिससे श्रमिकों को शीघ्र भुगतान हो सके ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

महत्वपूर्ण क्षेत्र (कोर सैक्टर) के संबंध में नीति

1716. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद महत्वपूर्ण क्षेत्र (कोर सैक्टर) के संबंध में केन्द्र सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार किन-किन उद्योगों को प्राथमिकता देने का विचार रखती है,

(ग) क्या सरकार कोर सैक्टर के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों को उत्पाद शुल्क में छूट या रेलवे माल भाड़े में छूट या अन्य वित्तीय छूटें देने का विचार रखती है; और

(घ) कोर सैक्टर उद्योगों में कार्यरत श्रमकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार, तीव्र औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के लिए उचित माहौल बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं खासतौर पर ऊर्जा, परिवहन, संचार और सिंचाई के क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जाएगा । बिजली, परिवहन और संचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जिन्हें उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार अधिक परिव्यय मिलना चाहिए, के लिए संसाधनों की कमी को इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश से पूरा करने की अपेक्षा की गई है । इन उपायों से जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति में घोषित उपायों में मदद मिलेगी। इस आशय को पूरा करने के लिए सरकार इन क्षेत्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वदेशी तथा विदेशी दोनों स्रोतों से निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश सक्रियता से आमंत्रित कर रही है ।

(ख) 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गए औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुबंध–II में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची दी गई है।

(ग) वर्ष 1993–94 के आगामी बजट को ध्यान में रखते हुए, उत्पाद शुल्क में छूट अथवा रेल भाड़े में छूट अथवा महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों के लिए कोई अन्य वित्तीय छूट देने के प्रस्तावों के बारे में इस अवस्था में सरकार की स्थिति का उल्लेख करना उचित नहीं होगा।

(घ) सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय मशीकरण निधि का उद्देश्य कोर क्षेत्र के उद्योगों सहित अन्य उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है जो औद्योगिक पुनर्निर्माण से प्रभावित हो सकते हैं।

Underpricing of Shares of Neyveli Lignite Corporation

1717. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Department of Public Enterprises underpriced the shares of the Neyveli Lignite Corporation at a rate of Rs. 17/-; and that the prices of shares shot up from Rs. 17 to Rs. 60—80 soon after the allotment thereof;

(b) if so, what are the reasons for underpricing of shares indicating the methodology was adopted in this case and the authority which tendered advice for fixing the price; and

(c) whether the Companies which purchased the shares of Neyveli Lignite Corporation at the rate of Rs. 17/- per share subsequently disposed of the same in public; if so, at what rate and quantum of such shares sold ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c) In October, 1992, Government offered 5% of the shares of NLC for sale and sold 1.04% of the shares at an average price of Rs. 23.40 per share. Government fixed the referal price of NLC shares @ Rs. 17/- per share based on the advice of the three major merchant bankers, viz., Industrial Credit and Investment Corpn. of India, Industrial Development Bank of India and SBI Capital Markets Ltd.

In October the NLC shares were quoted between Rs. 16 and Rs. 20 in the Madras Stock Exchange in some sporadic trading. The shares of NLC have since been traded in Stock Exchange very sporadically. No conclusion can or should be drawn based on a very limited trading as to under or overpricing of the shares.

The purchaser is free to off-load the shareholdings through the normal Stock Exchange trancactions.

1718. [*Transferred to 8th December*, 1992].

औद्योगिक विकास दर में गिरावट

1719. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 नवम्बर, 1992 को "आब्जर्वर" में "वरिड बाइ स्लम्प इन इनडस्ट्री" पी॰ एम॰ ओ॰ कालस स्पेशल मीट शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर निर्धारित लक्ष्य से कम होने की आशंका है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्य के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?